



The ACHIEVERS

IAS ACADEMY
PATNA

Daily NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Thursday, August 06, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- आरबीआई ने आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति जोखिमों के बीच तटस्थ नीति बनाए रखते हुए रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा
- लोकसभा ने केंद्र सरकार के व्यय के लिए समेकित निधि निकासी को अधिकृत करने वाले विनियोग विधेयक को पारित किया
- वित्त मंत्रालय ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान के लिए मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क को सक्षम करने वाला विधेयक पेश किया
- आईसीएआर ने पशुधन रोग से सुरक्षा के लिए भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित किया
- दिग्गज अभिनेता प्रदीप सिंह रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है।
- भारतीय वायुसेना ने रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए रोटर क्लैप III काउंटर-ड्रोन अभ्यास का समापन किया
- जीवीएमसी और मॉस्को ने स्मार्ट मोबिलिटी और सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- HDFC बैंक ने विशेष बैंकिंग लाभों के साथ वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बचतमैक्स खाते लॉन्च किए
- आरबीआई ने नई ऑन-टैप प्रणाली के माध्यम से शहरी सहकारी बैंक लाइसेंसिंग विंडो फिर से खोली
- बीईएल और ईएसआरआई इंडिया ने जीआईएस और जियोएआई रक्षा समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की

आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा



- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से अपने तटस्थ मौद्रिक नीति रुख को बनाए रखते हुए नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।
- यह निर्णय वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच आरबीआई के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- आरबीआई ने डेटा पर निर्भर मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

RBI ने रेपो दर को अपरिवर्तित क्यों रखा?

आरबीआई ने नीतिगत दर को निम्नलिखित कारणों से बनाए रखा:

- वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव।
- मुद्रास्फीति का दबाव, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति।
- घरेलू आर्थिक विकास को बनाए रखने की आवश्यकता है।
- एक सतर्क, डेटा-संचालित मौद्रिक नीति दृष्टिकोण।

रेपो दर क्या है?

- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

महत्व:

- भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक मौद्रिक नीति उपकरण।
- मुद्रास्फीति और तरलता को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- ऋण देने और जमा ब्याज दरों को प्रभावित करता है।
- उधार लेने की लागत, निवेश और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) भारत की नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करती है।

संरचना:

6 सदस्य:

• 3 आरबीआई से
• 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
• अध्यक्ष: RBI गवर्नर (पदेन अध्यक्ष)

कानूनी आधार:

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित।
- वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से स्थापित।

मौद्रिक नीति उपकरण:

RBI तरलता और मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है:

• साधन	उद्देश्य
• रेपो दर	आरबीआई ने बैंकों को दिया कर्ज
• रिवर्स रेपो/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)	RBI ने लिक्विडिटी को अवशोषित किया
• नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए नकदी भंडार
• वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	बैंकों द्वारा अनुरक्षित तरल परिसंपत्तियां
• सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)	बैंकों द्वारा आपातकालीन उधार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बारे में

• स्थापित	1 अप्रैल 1935
• राष्ट्रीयकृत	1 जनवरी 1949
• हेडक्वार्टर्स	मुंबई
• वर्तमान राज्यपालसंजय मल्होत्रा	

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा:

- भारत एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे का पालन करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- लक्षित CPI मुद्रास्फीति: 4%

सहिष्णुता बेंड: 2%-6%
वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ):

- 2022 में पेश किया गया।
- आरबीआई को संपार्श्विक प्रदान किए बिना तरलता को अवशोषित करने की अनुमति देता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को तरलता की कमी के दौरान RBI से रातोंरात उधार लेने में सक्षम बनाता है।
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): जमा का प्रतिशत जिसे बैंकों को आरबीआई के पास नकदी के रूप में बनाए रखना चाहिए।

परीक्षा फोकस बिंदु:

रेपो दर: 5.25%।
नीति रुख: तटस्थ।
निर्णय लेने वाली संस्था: मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)।
RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा।
एमपीसी का कानूनी आधार: आरबीआई अधिनियम, 1934 (धारा 45जेडबी)।
मुद्रास्फीति लक्ष्य: 4% (±2%)।
आरबीआई मुख्यालय: मुंबई।

लोकसभा ने भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए विनियोग विधेयक पारित किया



- लोकसभा ने विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जो केंद्र सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि (CFI) से निर्दिष्ट राशि की निकासी को अधिकृत करता है।
- यह विधेयक सरकार को लोकसभा में अनुदान मांगों पर मतदान के बाद स्वीकृत व्यय के लिए संचित निधि से कानूनी रूप से धन निकालने का अधिकार देता है।
- धन विधेयक के रूप में, अब इसे राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए पेश करने से पहले राज्यसभा की सिफारिश की आवश्यकता होती है।

विनियोग विधेयक क्या है?

- लोक सभा द्वारा अनुदान मांगों को पारित किए जाने के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। यह सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है।

महत्व:

- सरकारी धन को खर्च करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- केंद्रीय बजट को लागू करने के लिए आवश्यक।

- संसदीय अनुमोदन के बिना संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है।

भारत की संचित निधि (CFI):

- भारत की संचित निधि संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण सरकारी निधि है।
- संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 266(1)।

फंड के स्रोत:

कर राजस्व।
गैर-कर राजस्व।
सरकार द्वारा ऋण।
ऋण वसूली।

व्यय:

- वेतन और पेंशन।
- रक्षा व्यय।
- सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान।
- केंद्र सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम।

संवैधानिक प्रावधान:

आर्टिकल	विषय
अनुच्छेद 112	वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट)
अनुच्छेद 113	अनुदान की मांग
अनुच्छेद 114	विनियोग विधेयक

● अनुच्छेद 110 धन विधेयक

● अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता

सरकारी धन के प्रकार:

● निधि संवैधानिक प्रावधान उद्देश्य

● भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) सभी सरकारी राजस्व और व्यय

● भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 आपातकालीन व्यय

● भारत का सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 266(2) ट्रस्ट में रखा गया सार्वजनिक धन (जैसे, भविष्य निधि, छोटी बचत)

धन विधेयक:

● विनियोग विधेयक धन विधेयक है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित।
- इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया गया।
- राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है और इसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होगा।
- लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

अतिरिक्त तथ्य:

केंद्रीय बजट:

● अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।

● केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया।

से मिलकर बनता है:

● वार्षिक वित्तीय विवरण।

● अनुदान की मांग।

● वित्त विधेयक।

● विनियोग विधेयक।

● वित्त विधेयक बनाम विनियोग विधेयक

● वित्त विधेयक: बजट के कराधान प्रस्तावों को लागू करता है।

● विनियोग विधेयक: भारत की संचित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

● विधेयक: विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

● उद्देश्य: भारत की संचित निधि से धन की निकासी।

● संबंधित संवैधानिक लेख: अनुच्छेद 114.

● संचित निधि: अनुच्छेद 266(1)।

● धन विधेयक: अनुच्छेद 110

● केंद्रीय बजट: अनुच्छेद 112।

● अनुदान की मांग: अनुच्छेद 113।

वित्त मंत्रालय ने UPI और डिजिटल भुगतान पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) को सक्षम करने के लिए विधेयक पेश किया



● वित्त मंत्रालय ने निर्दिष्ट UPI और अन्य डिजिटल भुगतान लेनदेन पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए

संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है।

- विधेयक तुरंत एमडीआर लागू नहीं करता है, लेकिन सरकार और नियामकों को भविष्य में इस तरह के शुल्कों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा करते हुए भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित एमडीआर, यदि पेश किया जाता है, तो केवल बड़े व्यापारियों और उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर लागू हो सकता है, जिसमें व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा।

मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) क्या है?

- मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वह शुल्क है जो किसी व्यापारी द्वारा डिजिटल भुगतान लेनदेन को संसाधित करने के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- व्यापारी द्वारा भुगतान किया जाता है, ग्राहक द्वारा नहीं।
- भुगतान प्रसंस्करण, निपटान, धोखाधड़ी की रोकथाम और बुनियादी ढांचे की लागत को कवर करता है।
- आमतौर पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन पर शुल्क लिया जाता है।
- जनवरी 2020 से, यूपीआई और रुपये डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर शून्य है।

संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है?

सरकार इस संशोधन पर विचार कर रही है क्योंकि:

- यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
- बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बढ़ती प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की लागत का सामना करना पड़ता है।
- भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल की आवश्यकता है।
- संशोधन वित्तीय समावेशन को प्रभावित किए बिना जहां आवश्यक हो, एमडीआर शुरू करने की सुविधा प्रदान करता है।

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के बारे में:

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित भारत की वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली है।

सुविधाएँ:

- तत्काल 24x7 फंड ट्रांसफर।
- बैंकों में इंटरऑपरेबल।
- व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान का समर्थन करता है।
- मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करता है।

- जुलाई 2026 में, UPI ने लगभग ₹29.9 लाख करोड़ के 23.6 बिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी रीयल-टाइम भुगतान प्रणालियों में से एक बन गया।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई):

- स्थापित:2008
- प्रकार: खुदरा भुगतान के लिए छाता संगठन
- द्वारा प्रचारित: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA)
- मुख्यालय: मुंबई
- एमडी और सीईओ: दिलीप आण्णे

प्रमुख उत्पाद

- यूपीआई।
- रुपे।
- भीमा।
- आईएमपीएस।
- नचा।
- फास्टैग
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

द्वारा विनियमित

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।

उद्देश्य

- भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करें।
- भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को अधिकृत करें।
- डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करें।

भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी):

- लॉन्च किया गया: 30 दिसंबर 2016।
- एनपीसीआई द्वारा विकसित।
- यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित।
- रुपे
- भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क।
- एनपीसीआई द्वारा विकसित।
- 2012 में लॉन्च किया गया।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- विधेयक: भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2026 - उद्देश्य: डिजिटल भुगतान पर एमडीआर के लिए कानूनी ढांचे को सक्षम करना। - एमडीआर: डिजिटल लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यापारियों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क। - डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म: यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)। - द्वारा विकसित: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)।	- नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)। - मूल कानून: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007। - भीम लॉन्च: 30 दिसंबर 2016 - रुपे लॉन्च: 2012।
--	--

आईसीएआर ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया



- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है, जो पशु चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी और पशुधन रोग नियंत्रण में एक बड़ी सफलता है।
- एमए-104 सेल-आधारित लाइव एटेन्यूएटेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन नाम के इस टीके को आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सेक्योरिटी एनिमल डिजीज (एनआईएचएसडी), भोपाल द्वारा विकसित किया गया है।
- यह घरेलू सूअरों को अत्यधिक संक्रामक एएसएफ वायरस से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसने विशेष रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुअर पालन क्षेत्र को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।
- वैक्सीन से भारत की जैव सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने और पशुधन अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की उम्मीद है।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के बारे में:

- अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- प्रेरक एजेंट: अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस (एएसएफवी)। - प्रभावित जानवर: घरेलू सूअर और जंगली सूअर। - मृत्यु दर: लगभग 100% तक पहुंच सकती है। - संचरण: सीधा संपर्क, दूषित चारा, संक्रमित सूअर का मांस उत्पाद और नरम टिका।
--

- मानव स्वास्थ्य: मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है और खाद्य सुरक्षा जोखिम नहीं है।

ICAR के बारे में:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए भारत का शीर्ष निकाय है।
- स्थापित: 16 जुलाई 1929
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- डायरेक्टर: मांगी लाल जाट
- अध्यक्ष: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री (शिवराज सिंह चौहान)

ICAR-NIHSAD के बारे में:

- ICAR-National Institute of High Security Animal Diseases (NIHSAD) स्थित हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में।

कार्य:

- उच्च जोखिम वाले पशु रोगों पर अनुसंधान।
- वैक्सीन और नैदानिक विकास।
- रोग निगरानी।
- पशुधन जैव सुरक्षा को मजबूत करना।

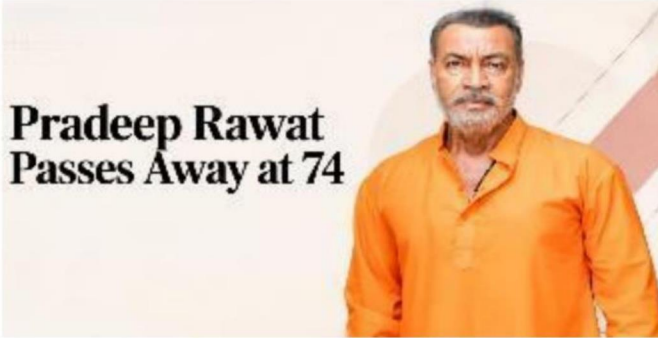
परीक्षा फोकस बिंदु:

- रोग: अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ)। - द्वारा विकसित: आईसीएआर-एनआईएचएसडी, भोपाल। - वैक्सीन: एमए -104 सेल-आधारित लाइव क्षीण एएसएफ वैक्सीन। - लक्षित जानवर: घरेलू और जंगली सूअर। - मृत्यु दर: 100% तक। - मानव संक्रमण: नहीं। - आईसीएआर मुख्यालय: नई दिल्ली।
--

- आईसीएआर की स्थापना: 16 जुलाई 1929।

दिग्गज अभिनेता प्रदीप सिंह रावत का 74 साल की उम्र में निधन

Pradeep Rawat Passes Away at 74



- गजनी, लगान और बीआर चोपड़ा की महाभारत में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले दिग्गज भारतीय अभिनेता प्रदीप सिंह रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- उन्हें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी सिनेमा में यादगार प्रतिपक्षी भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया था।

करियर हाइलाइट्स

- प्रदीप रावत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीआर चोपड़ा के टेलीविजन धारावाहिक महाभारत से की थी, जहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था।

बाद में उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए राष्ट्रव्यापी पहचान प्राप्त की:

- लगान (2001) - देवा सिंह की भूमिका निभाई।
- हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में बड़े पैमाने पर अभिनय किया।

पुरस्कार:

- 2004: विजेता, साई के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार (तेलुगु)
- 2004: विजेता, संतोषम सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार
- 2004: विजेता, साई के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए नंदी पुरस्कार

परीक्षा फोकस बिंदु:

- पर्सन: प्रदीप सिंह रावत।
- के लिए जाना जाता है: गजनी, लगान और महाभारत।
- आइकॉनिक टीवी भूमिका: अश्वत्थामा।
- सर्वोच्च भारतीय सिनेमा पुरस्कार: दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: 1954 में स्थापित।
- आईएफएफआई स्थान: गोवा।

- गजनी (2008) - विरोधी गजनी धर्मात्मा की भूमिका निभाई।

भारतीय वायु सेना ने राजस्थान में ड्रोन रोधी अभ्यास रोटर क्लैप III का समापन किया



- भारतीय वायु सेना (IAF) ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक सप्ताह तक चलने वाले काउंटर-ड्रोन अभ्यास ROTOR CLAP III का सफलतापूर्वक समापन किया।
- यह अभ्यास शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAS) का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और बेअसर करने के लिए IAF की क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।

- इसने उभरते ड्रोन और झुंड ड्रोन खतरों के खिलाफ भारत की तैयारियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं।

काउंटर-ड्रोन तकनीक क्या है?

- काउंटर-ड्रोन सिस्टम को अनधिकृत या शत्रुतापूर्ण ड्रोन का पता लगाने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख घटक:

- रडार-आधारित पहचान।
- इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर।
- रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) जैमर।
- जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग।

- निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs), जिसमें लेजर सिस्टम भी शामिल हैं। - हार्ड-किल सिस्टम जैसे मिसाइल और एंटी-ड्रोन गन।	प्रशिक्षण कमान – बेंगलुरु
---	---

काउंटर-ड्रोन क्षमता का महत्व:

- निगरानी, टोही और हमलों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने काउंटर-ड्रोन सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बना दिया है।

अनुप्रयोगों

- सीमा सुरक्षा।
- एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।
- आतंकवाद विरोधी अभियान।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा।
- आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन अभियान।

भारतीय वायु सेना (IAF) के बारे में:

- स्थापना: 8 अक्टूबर 1932 - मुख्यालय: नई दिल्ली - आदर्श वाक्य: नाभा: स्पर्शम् दीप्तम् ("महिमा के साथ आकाश को छूएं") - चीफ: चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एयर चीफ मार्शल)

प्रमुख आदेश:

- पश्चिमी वायु कमान – नई दिल्ली। - पूर्वी वायु कमान – शिलांग। - दक्षिणी वायु कमान – तिरुवनंतपुरम। - दक्षिण पश्चिमी वायु कमान – गांधीनगर। - सेंट्रल एयर कमांड – प्रयागराज। - मेटेनैस कमांड – नागपुर।
--

पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में:

- राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है।
- भारत के प्रमुख सैन्य परीक्षण और फायरिंग रेंज में से एक।
- वायु शक्ति जैसे प्रमुख सैन्य अभ्यासों की मेजबानी करता है।
- भारत के पोखरण-1 (1974) और पोखरण-2 (1998) परमाणु परीक्षणों के लिए भी जाना जाता है।

अतिरिक्त:

- वायु शक्ति अभ्यास
- भारतीय वायु सेना का एक प्रमुख मारक क्षमता प्रदर्शन अभ्यास।
- पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया।
- यह भारतीय वायुसेना की हवाई लड़ाई, सटीक हमले और एकीकृत युद्ध क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- व्यायाम: रोटर क्लैप III। - द्वारा संचालित: भारतीय वायु सेना। - स्थान: पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर (राजस्थान)। - उद्देश्य: काउंटर-ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाना। - संबंधित व्यायाम: वायु शक्ति। - भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य: नभाह स्पर्श दीप्तम्। - भारतीय वायुसेना की स्थापना: 8 अक्टूबर 1932।
--

जीवीएमसी और मॉस्को ने विशाखापत्तनम में स्मार्ट मोबिलिटी और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



- ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC) और मॉस्को सरकार ने विशाखापत्तनम (विजाग), आंध्र प्रदेश में स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल इनोवेशन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) और सतत शहरी विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- साझेदारी का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और विजाग में नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ाने के लिए शहरी गतिशीलता, यातायात प्रबंधन और स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों में मास्को की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।

- यह समझौता भारत के स्मार्ट सिटी मिशन और व्यापक शहरी परिवर्तन पहल के अनुरूप है।

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में:

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- शुरू किया गया: 25 जून 2015
- उद्देश्य: 100 नागरिक-अनुकूल, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-सक्षम शहरों का विकास करना

मुख्य घटक

- स्मार्ट गतिशीलता।
- इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस)।
- ई-गवर्नेंस।
- जल और अपशिष्ट प्रबंधन।
- ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचा।
- डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं।

GVMC के बारे में:

- ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) शहरी स्थानीय निकाय है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

कार्य:

- शहरी नियोजन।
- सार्वजनिक परिवहन और सड़क बुनियादी ढांचा।
- जल आपूर्ति और स्वच्छता।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं।

इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस):

- एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) परिवहन बुनियादी ढांचे के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) को एकीकृत करता है।

फायदे:

- स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल।
- वास्तविक समय यातायात निगरानी।
- भीड़ में कमी।
- बेहतर सड़क सुरक्षा।
- कुशल सार्वजनिक परिवहन।
- कम ईंधन की खपत और उत्सर्जन।

विशाखापत्तनम के बारे में:

- राज्य: आंध्र प्रदेश
- लोकप्रिय नाम: विजाग
- तट: बंगाल की खाड़ी
- प्रमुख बंदरगाह: विशाखापत्तनम बंदरगाह
- महत्व: प्रमुख बंदरगाह शहर, औद्योगिक और नौसेना केंद्र

परीक्षा फोकस बिंदु:

- समझौता ज्ञापन भागीदार: जीवीएमसी और मॉस्को सरकार।
- शहर: विशाखापत्तनम (विजाग)।
- फोकस: स्मार्ट गतिशीलता और डिजिटल शहरी विकास।
- संबंधित योजना: स्मार्ट सिटी मिशन।
- लॉन्च वर्ष: 2015।
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- प्रासंगिक संविधान संशोधन: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।
- प्रासंगिक अनुसूची: बारहवीं अनुसूची।

HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत और अपने बचत खातों के लिए Max लॉन्च किया

- एचडीएफसी बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की विशिष्ट वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन शैली और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमशः दो नए अनुकूलित बचत खाता वेरिएंट- सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स और सेविंग्समैक्स फॉर हर लॉन्च किए हैं।

- यह पहल सेगमेंट-आधारित बैंकिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो पारंपरिक बैंकिंग से परे उन्नत मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ व्यक्तिगत उत्पादों की पेशकश करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत मैक्स की विशेषताएं:

वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, खाता प्रदान करता है:

- मानार्थ डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं।
- उच्च सावधि जमा (एफडी) ब्याज दरें (जैसा लागू हो)।
- स्वास्थ्य देखभाल और फार्मसी से संबंधित छूट।
- बीमा लाभ और प्रीमियम डेबिट कार्ड सुविधाएं।
- पार्टनर ब्रांडों से विशेष ऑफर।



उसके लिए SavingsMax की विशेषताएं:

विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया, खाता प्रदान करता है:

- जीवनशैली और कल्याण लाभ।
- स्वास्थ्य और बीमा कवरेज।
- कैशबैक और डेबिट कार्ड ऑफर।
- स्वचालित स्वीप सुविधा (मनी मैक्सिमाइज़र)।
- विशेष भागीदार छूट और वित्तीय लाभ।

HDFC बैंक के बारे में:

- स्थापित: 1994
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- एमडी और सीईओ: शशिधर जगदीशन

भारत में वित्तीय समावेशन:

प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)
- डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)
- बिजनेस कॉरस्पॉण्डेंट (बीसी) मॉडल।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- बैंक: एचडीएफसी बैंक।
- नए खाते: वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत और उसके लिए बचतमैक्स।
- लक्षित समूह: वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं।
- क्षेत्र: व्यक्तिगत खुदरा बैंकिंग।
- बैंकिंग नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।
- एचडीएफसी बैंक मुख्यालय: मुंबई।

आरबीआई नए शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) लाइसेंस के लिए खिड़की फिर से खोलेगा



- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि वह दो दशकों से अधिक के अंतराल के बाद शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को नए लाइसेंस देने के लिए खिड़की फिर से खोलेगा।

- आरबीआई ने एक 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने की भी योजना बनाई है, जिससे पात्र संस्थाओं को विशिष्ट लाइसेंसिंग विंडो की प्रतीक्षा करने के बजाय पूरे वर्ष लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके।
- यह निर्णय जनवरी 2026 में जारी शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग पर चर्चा पत्र पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना है।

ऑन-टैप लाइसेंसिंग क्या है?

- ऑन-टैप लाइसेंसिंग पात्र आवेदकों को नियामक द्वारा घोषित एक विशिष्ट आवेदन विंडो की प्रतीक्षा करने के बजाय किसी भी समय लाइसेंस आवेदन जमा करने की अनुमति देता है।

फ़ायदे:

● पात्र संस्थानों का निरंतर प्रवेश।
● तेज़ लाइसेंसिंग प्रक्रिया।
● अधिक पारदर्शिता।
● व्यापार करने में आसानी में सुधार।

शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के बारे में

- शहरी सहकारी बैंक सहकारी वित्तीय संस्थान हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की सेवा करते हैं।

सुविधाएँ:

● राज्य सहकारी समिति अधिनियमों या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत।
● बैंकिंग कार्यों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित।
● बचत खाते, जमा, ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करें।
● छोटे व्यवसायों, व्यापारियों, वेतनभोगी व्यक्तियों और मध्यम आय समूहों पर ध्यान केंद्रित करें।

नए लाइसेंस क्यों बंद किए गए?

आरबीआई ने 2004 में नए यूसीबी लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया था:

● कई यूसीबी का कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य।
● शासन के मुद्दे।
● खराब पूंजी पर्याप्तता।
● बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)।
● कमजोर जोखिम प्रबंधन प्रणाली।
● नियामकीय सुधारों और गवर्नेंस में सुधार के बाद आरबीआई ने अब लाइसेंसिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

RBI का चर्चा पत्र (2026):

बीईएल और ईएसआरआई इंडिया ने जीआईएस और जियोएआई प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की

यह खबरों में क्यों है?

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने भारत के रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और जियोएआई समाधान विकसित करने के लिए Esri इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम

- शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस पर आरबीआई के चर्चा पत्र में प्रस्ताव किया गया है:
- वित्तीय रूप से मजबूत सहकारी ऋण समितियों को लाइसेंस देना।
- ₹300 करोड़ की न्यूनतम पूंजी वाले संस्थानों को वरीयता।
- वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए व्यापक भौगोलिक उपस्थिति।
- लाइसेंस देने से पहले मजबूत शासन और नियामक अनुपालना।

निर्णय महत्वपूर्ण क्यों है?

इस कदम से उम्मीद की जाती है:

● शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच का विस्तार करना।
● वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
● सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
● सुशासित सहकारी ऋण समितियों को बैंक बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
● शहरी सहकारी बैंकों के लचीलेपन और स्थिरता को मजबूत करना।

परीक्षा फोकस बिंदु:

● नियामक: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)।
● निर्णय: शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग को फिर से शुरू करना।
● नई प्रणाली: ऑन-टैप लाइसेंसिंग।
● पिछला लाइसेंसिंग रोक: 2004।
● चर्चा पत्र: जनवरी 2026।
● पसंदीदा आवेदक: बड़ी सहकारी ऋण समितियां।
● संबंधित कानून: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020।
● जमा बीमा एजेंसी: DICGC।
● जमा बीमा सीमा: ₹5 लाख।

बुद्धिमत्ता का उपयोग करके निर्णय लेने, निगरानी, मिशन योजना और स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करना है।

मुख्य बिंदु

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और एसरी इंडिया ने रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह साझेदारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा के लिए जीआईएस और जियोएआई-आधारित समाधान विकसित करेगी।
- प्रौद्योगिकियां वास्तविक समय मानचित्रण, निगरानी, खुफिया विश्लेषण, मिशन योजना और परिसंपत्ति प्रबंधन का समर्थन करेंगी।



बीईएल के बारे में

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) रक्षा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (डीपीएसयू) है। 1954 में स्थापित, बीईएल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करता है, जिसमें रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा नेटवर्क शामिल हैं।

जीआईएस क्या है?

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग भौगोलिक या स्थानिक डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह मानचित्रण, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, रक्षा योजना और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है।

जियोएआई क्या है?

- जियोएआई (जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भू-स्थानिक डेटा जैसे उपग्रह इमेजरी, मानचित्र, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग के साथ जोड़ता है। यह निर्णय लेने, खतरे का पता लगाने और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण में सुधार के लिए बड़ी मात्रा में स्थान-आधारित डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है।

महत्व

- यह साझेदारी भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता के साथ एआई को एकीकृत करके भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाएगी। यह विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करते हुए परिचालन दक्षता, सीमा निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया और रणनीतिक योजना में सुधार करेगा।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और Esri India के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- उद्देश्य: रक्षा के लिए जीआईएस और जियोएआई समाधान विकसित करना।
- बीईएल स्थिति: नवरत्न रक्षा पीएसयू।
- मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय।
- प्रयुक्त प्रौद्योगिकी: जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) और जियोएआई (भू-स्थानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता)।
- अनुप्रयोग: निगरानी, मानचित्रण, मिशन योजना, खुफिया विश्लेषण और परिसंपत्ति प्रबंधन।
- समर्थन करता है: रक्षा में आत्मनिर्भर भारत।

बीईएल

- स्थापित: 1954
- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: मनोज जैन

आगे की राह

- एआई-संचालित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करना, स्वदेशी रक्षा नवाचार को मजबूत करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा।

लेट्स रिवाइज

- ❖ आरबीआई ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो दर को किस दर पर बरकरार रखा है? **5.25%**
- ❖ कौन सा विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकालने को अधिकृत करता है? विनियोग **विधेयक**
- ❖ डिजिटल भुगतान पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा विधेयक पेश किया गया था? **भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2026**
- ❖ आईसीएआर द्वारा विकसित स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन का नाम क्या है? **एमए -104 सेल-आधारित लाइव क्षीण अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन**
- ❖ हाल ही में गजनी और लगान के लिए जाने जाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया? **प्रदीप सिंह रावत**
- ❖ ROTOR CLAP III अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? **राजस्थान**
- ❖ किस भारतीय शहर ने हाल ही में स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मॉस्को सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? **विशाखापत्तनम (विजाग)**
- ❖ किस बैंक ने हाल ही में अपने बचत खातों के लिए वरिष्ठ नागरिकों और बचतमैक्स के लिए बचत मैक्स लॉन्च किया है? **एचडीएफसी बैंक**
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए किस लाइसेंसिंग प्रणाली का प्रस्ताव किया है? **ऑन-टैप लाइसेंसिंग**
- ❖ भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए जीआईएस और जियोआई समाधान विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और एसरी इंडिया**
- ❖ बीईएल-एसरी इंडिया साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? **रक्षा, मातृभूमि सुरक्षा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए जीआईएस और जियोआई-आधारित समाधान विकसित करना**
- ❖ जीआईएस का क्या अर्थ है? **भौगोलिक सूचना प्रणाली**



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA